International Journal of Economic Perspectives,*19* (12) 21-37
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

वनोपज-आधारित आजीविका और न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति का बैगा जनजातीय सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव: छत्तीसगढ़ के कवर्धा (कबीरधाम) ज़िले के ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन

शोधार्थी
घुरवा राम श्याम[1]
अर्थशास्त्र विभाग, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय- दुर्ग, (छत्तीसगढ़)

शोध निर्देशक
प्रो. (डॉ.) आर. एन. सिंह[2]
अर्थशास्त्र विभाग, पूर्व प्राचार्य,
शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय- दुर्ग, (छत्तीसगढ़)

शोध सार

यह अध्ययन छत्तीसगढ़ के कवर्धा ज़िले के बोड़ला और पंडरिया ब्लॉकों के गावों में वनोपज-आधारित आजीविका, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नीति तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। दोनों क्षेत्र उच्च वन-आवरण और बड़ी बैगा जनजातीय आबादी वाले हैं जहाँ आय के प्रमुख स्रोत कृषि, मजदूरी और वनोपज हैं। अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक आकड़ों का मिश्रित प्रयोग किया गया। प्राथमिक डेटा को समेकित रूप में विश्लेषित किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका विविधीकरण, कार्य-दिवस प्रतिरूप, उपभोग, अवसंरचना, वनोपज निर्भरता, MSP जागरूकता और बाजार मूल्य असंगति जैसे तत्वों को वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास किया गया। परिणाम दर्शाते हैं कि पंडरिया शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में अधिक वंचित है तथा वनोपज पर अधिक निर्भरता वाला विकासखंड है। MSP की जागरूकता मात्र 12-20 प्रतिशत लोगों में पाई गई, जिससे बिचौलिया-निर्भरता और आय-हानि बढ़ जाती है। चरोटा, वनजीरा, डोरी जैसे उत्पादों में MSP बाजार की तुलना में कम है, जबकि लाख और शहद में MSP अधिक है लेकिन संग्रहण मात्रा सीमित रहती है। अध्ययन यह निष्कर्ष देता है कि दोनों विकासखंडों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति कमजोर है और वनोपज-आधारित MSP नीति को प्रभावी बनाने हेतु बाजार-संगत मूल्य, प्रसंस्करण इकाइयों और सूचना-तंत्र की आवश्यकता है। यह शोध नीति-निर्माण और क्षेत्रीय विकास के लिए उपयोगी साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द: *वनोपज-आधारित आजीविका, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का प्रभाव, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, बैगा जनजाति*

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2025, Revised: 09 Nov 2025, Accepted: 18 Nov 2025, Published: Dec 2025

International Journal of Economic Perspectives,*19* **(12) 21-37**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

परिचय

भारत की जनजातीय अर्थव्यवस्था वनों और वनोपज पर आधारित एक दीर्घ ऐतिहासिक प्रणाली के रूप में विकसित हुई है। देश में 100 मिलियन से अधिक लोग मुख्यतः जनजातीय समुदाय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लघु वनोपज Minor Forest Produce (MFP) पर अपनी आजीविका निर्भर करते हैं (Tiwari, 2021)। इस प्रणाली में वनोपज न केवल पूरक आय देता है बल्कि सामाजिक सुरक्षा, मौसमी रोजगार और खाद्य-पोषण की भी भूमिका निभाता है। वनोपज की विशेषता यह है कि इसका संग्रहण कम पूँजी, अधिक श्रम और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित होता है, इसलिए यह ग्रामीण-जनजातीय जीवन के केंद्र में बना रहता है।

छत्तीसगढ़ का कबीरधाम जिला, विशेषकर बोड़ला और पंडरिया विकासखंड, इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ बैगा जनजातीय आबादी का अनुपात अधिक है, वन-आवरण व्यापक है और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क तथा बाजार पहुँच जैसे अवसंरचात्मक तत्व अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति हैं। इस कारण आय-जोखिम, बाजार-शोषण और योजनागत वंचना की आशंका अधिक हो जाती है। वनोपज आय अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि इसका उत्पादन और विपणन वर्षा, तापमान, वनाग्नि, जैव-विविधता और नीति परिवर्तनों पर निर्भर करता है (Banerjee & Behera, 2019)। इन परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नीति को लागू किया ताकि जनजातीय परिवारों को न्यूनतम आय-सुरक्षा प्राप्त हो सके।

हालाँकि MSP नीति का उद्देश्य स्पष्ट है, परंतु इसका वास्तविक प्रभाव क्षेत्र-विशेष में कैसा है, इसका पर्याप्त अध्ययन उपलब्ध नहीं है। यह अध्ययन इस अंतर को भरता है और दोनों ब्लॉकों के लोगों की आजीविका संरचना, MSP जागरूकता, बाजार मूल्य अंतर और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। अध्ययन विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पंडरिया और बोड़ला में वनोपज संग्रहण की मात्रा, बाजार संपर्क, आजीविका विविधीकरण और योजनागत पहुँच में उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है। इन दोनों क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन यह समझने में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि देता है कि वनोपज-आधारित नीतियाँ, MSP निर्धारण और बाजार संरचना ग्रामीण जीवन की अस्थिरता और अवसरों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

इस शोध का उद्देश्य क्षेत्र-विशिष्ट तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर नीति-निर्माताओं को उपयोगी सिफारिशें प्रदान करना है। परिणाम न केवल वनोपज-आधारित अर्थव्यवस्था को गहराई से समझने में मदद करेंगे बल्कि यह भी स्पष्ट करेंगे कि MSP और अन्य योजनाएँ स्थानीय स्तर पर कितनी प्रभावी हैं।

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2025, Revised: 09 Nov 2025, Accepted: 18 Nov 2025, Published: Dec 2025

International Journal of Economic Perspectives,*19* **(12) 21-37**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

साहित्य समीक्षा

भारत में वनोपज-आधारित आजीविका पर व्यापक साहित्य उपलब्ध है जो दर्शाता है कि गैर-लकड़ी वन उत्पाद (NTFP) ग्रामीण-जनजातीय परिवारों के लिए मौसमी और स्थायी आय का मुख्य स्रोत है (Gupta & Kant, 2018)। कई अध्ययनों में यह उल्लेखित है कि वनोपज महिलाओं, युवाओं और छोटे किसानों के लिए कम बाधा वाला आर्थिक अवसर प्रदान करता है (Rao, 2019)। हालाँकि बाजार-असंगति, बिचौलियों का नियंत्रण और मूल्य-सूचना की कमी संग्रहकर्ताओं की आय को सीमित करते हैं (Saxena, 2020)।

MSP नीति को इस समस्या का समाधान माना गया, परंतु TRIFED (2022) और Ministry of Tribal Affairs (2021) की रिपोर्टें दर्शाती हैं कि MSP का लाभ उन क्षेत्रों में ही अधिक मिलता है जहाँ खरीद-केन्द्र सुलभ हों और स्थानीय संस्थागत संरचना मजबूत हो। कई शोध यह भी दर्शाते हैं कि MSP की जागरूकता कम होने से अधिकांश वनोपज संग्रहकर्ता वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते (Sharma, 2017)।

वनोपज निर्भरता और सामाजिक-आर्थिक वंचना के बीच संबंध को कई अध्ययनों ने रेखांकित किया है। कम शिक्षा, कम बाजार संपर्क और कमजोर अवसंरचना वनोपज संग्रहकर्ताओं को उच्च जोखिम की स्थिति में रखती है (Meena, 2015)। हालाँकि जिला-स्तरीय तुलनात्मक अध्ययनों की कमी है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ वनोपज आय कुल पारिवारिक आय का महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यह अध्ययन इसी शोध-रिक्ति को पूरा करता है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा (कबीरधाम) ज़िले के बोड़ला और पंडरिया विकासखंडों के चयनित ग्रामों में किया गया है। यह ज़िला मध्य भारत के वन-प्रधान क्षेत्रों में स्थित है और यहाँ का भौगोलिक परिदृश्य पठारी भागों, घने वनों और वर्षा-आधारित कृषि पर आधारित है। अध्ययन क्षेत्र में बैगा, गोंड और अन्य जनजातीय समुदायों की आबादी अधिक है, जिनकी आजीविका मुख्यतः कृषि, मजदूरी और वनोपज संग्रहण पर निर्भर करती है। बोड़ला और पंडरिया दोनों विकासखंडों में वन-आवरण व्यापक है, जिससे महुआ, तेंदूपत्ता, साल बीज, लाख, शहद, चरोटा और अन्य वनोपज प्रमुख आय स्रोत बनते हैं। हालांकि, क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बाजार और बैंकिंग जैसी बुनियादी सुविधाएँ सीमित हैं। विशेष रूप से पंडरिया विकासखंड में सामाजिक-आर्थिक वंचना, वनोपज निर्भरता और योजनागत पहुँच की समस्याएँ अधिक गंभीर हैं। यही कारण है कि यह क्षेत्र वनोपज-आधारित आजीविका और MSP नीति के प्रभाव के अध्ययन के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया है।

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2025, Revised: 09 Nov 2025, Accepted: 18 Nov 2025, Published: Dec 2025

***International Journal of Economic Perspectives*,19 (12) 21-37**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

उदेस्श्य

1. बोड़ला और पंडरिया की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक मूल्यांकन करना।
2. वनोपज-आधारित आजीविका, कार्य-दिवस पैटर्न और आय विविधीकरण को समझना।
3. MSP और बाजार-मूल्य असंगति का वर्ग-वार और उत्पाद-वार विश्लेषण करना।
4. सरकारी योजनाओं की पहुँच और प्रभाव का मूल्यांकन कर नीतिगत सुझाव देना।

शोध पद्धति

अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक आँकड़ों का संयुक्त उपयोग किया गया। प्राथमिक आँकड़े गोपनीय रूप में एकत्र किए गए और विश्लेषण के लिए केवल समेकित रूप में प्रयोग हुए। द्वितीयक स्रोतों में TRIFED, NSSO, Forest Department, IIFM, MoTA और अनेक शोध–पत्र शामिल थे। अनुसंधान रूपरेखा मिश्रित पद्धति पर आधारित थी, जिसमें सर्वेक्षण, साक्षात्कार और अवलोकन से डेटा संग्रह किया गया। इसके बाद वर्णनात्मक आँकड़ों, प्रतिशत, औसत और विषयगत विश्लेषण का उपयोग कर शिक्षा, आजीविका, MSP और योजनागत पहुँच के पैटर्न पहचाने गए। तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से बोड़ला और पंडरिया के बीच सामाजिक–आर्थिक अंतर को समझा गया। MSP और बाजार–मूल्य के बीच अंतर का मूल्यांकन उत्पाद–वार तुलना और मूल्य–अंतर विश्लेषण द्वारा किया गया। परिणामों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए त्रिकोणीयकरण अपनाया गया, जिसमें फील्ड-नोट्स, द्वितीयक स्रोत और प्राथमिक निष्कर्षों का परस्पर सत्यापन शामिल था।

अनुसंधान रूपरेखा

तालिका 1: अनुसंधान अभिकल्प

चरण	विवरण	विधि
आँकड़ा संग्रह	प्राथमिक + द्वितीयक	सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन
विश्लेषण	वर्णनात्मक + तुलनात्मक	प्रतिशत, औसत, विषयगत विश्लेषण
MSP मूल्यांकन	मूल्य–अंतर विश्लेषण	उत्पाद–वार MSP बनाम बाजार तुलना
सत्यापन	त्रिकोणीयकरण	स्रोत–तुलना और फील्ड नोट्स

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2025, Revised: 09 Nov 2025, Accepted: 18 Nov 2025, Published: Dec 2025

***International Journal of Economic Perspectives*,19 (12) 21-37**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

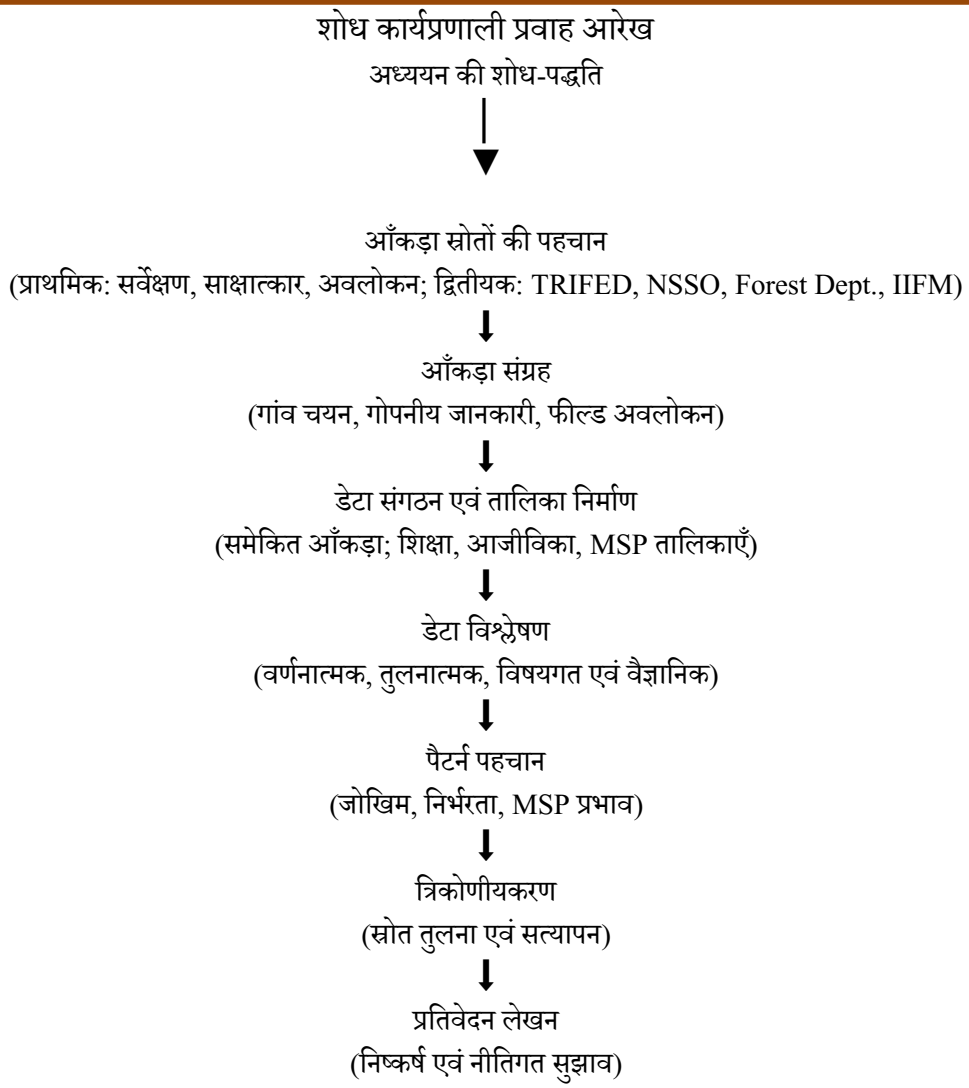

आँकड़ा का स्वरूप

अध्ययन में प्राथमिक आँकड़ा और द्वितीयक स्रोतों का संयुक्त उपयोग किया गया। तालिकाएँ केवल रूप में प्रस्तुत हैं। द्वितीयक स्रोतों में TRIFED, NSSO, Forest Department, IIFM, MoTA तथा विभिन्न शोध-पत्र शामिल हैं।

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2025, Revised: 09 Nov 2025, Accepted: 18 Nov 2025, Published: Dec 2025

International Journal of Economic Perspectives,*19* (12) 21-37
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

तुलनात्मक विश्लेषण

तालिका 2: तुलनात्मक विश्लेषणात्मक स्वरुप

सूचक	बोड़ला	पंडरिया	तुलना का उद्देश्य
शिक्षा	मध्यम	कमजोर	मानव–पूंजी स्थिति
आजीविका	मिश्रित	वनोपज–उच्च	जोखिम–निर्भरता
MSP जागरूकता	कम	बहुत कम	बाजार–शोषण समझना
योजनाएँ	बेहतर पहुँच	कमजोर पहुँच	अवसंरचना अंतर

अध्ययन-सीमाएँ

1.प्राथमिक डेटा गोपनीयता के कारण पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
वनोपज की उपलब्धता पर्यावरणीय उतार-चढ़ाव पर निर्भर होने से डेटा गतिशील है।

सामाजिक-जनसांख्यिकीय स्थिति

तालिका 3 : शैक्षणिक स्थिति

श्रेणी	प्रतिशत (राउंडेड)
अशिक्षित	~70%
प्राथमिक	~19%
माध्यमिक	~7%
उच्चतर	~4%
कुल निष्कर्ष	~89% प्राथमिक से नीचे

विश्लेषण: भाग-एक

संग्रहित आंकड़ों से स्पष्ट है कि बोड़ला और पंडरिया दोनों ब्लॉक गंभीर शिक्षा वंचना का सामना कर रहे हैं। लगभग 70 प्रतिशत परिवार-प्रधान अशिक्षित पाए गए, जो राष्ट्रीय ग्रामीण औसत (MoSPI, 2020) की तुलना में बहुत अधिक है। यह शिक्षा अंतर केवल सांख्यिकीय विसंगति नहीं बनता, बल्कि समग्र आजीविका ढांचे को प्रभावित करने वाला मूलभूत कारक

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2025, Revised: 09 Nov 2025, Accepted: 18 Nov 2025, Published: Dec 2025

***International Journal of Economic Perspectives*,19 (12) 21-37**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

है। उच्च विद्यालय शिक्षा तक पहुँच दोनों क्षेत्रों में सीमित है, लेकिन पंडरिया में स्थिति और गंभीर है। इसका कारण भौगोलिक दूरी, खराब संपर्क, सीमित परिवहन साधन और स्कूल अवसंरचना की कमी है। साक्षात्कारों में माता पिता ने बताया कि ऊपरी प्राथमिक से ऊपर की शिक्षा आर्थिक रूप से वहन करना कठिन है, जिसके कारण बच्चों को श्रम में लगना पड़ता है।

कम शिक्षा से आय अवसरों में उल्लेखनीय कमी आती है। वनोपज संग्रह, मजदूरी और मौसमी कृषि–श्रम इन परिवारों का मुख्य आर्थिक आधार हैं, जिनमें आय का स्तर अनिश्चित और अत्यधिक जोखिमयुक्त होता है। पंडरिया में पारंपरिक वन ज्ञान समृद्ध है, परंतु औपचारिक शिक्षा के अभाव में यह कौशल आधुनिक बाजार से मेल नहीं खा पाता। प्रशिक्षण, ग्रेडिंग ज्ञान, मूल्य सूचना पढ़ने की क्षमता और MSP समझने की योग्यता भी शिक्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि MSP जागरूकता 12-20 प्रतिशत के बीच सीमित है और कई परिवार यह पहचान ही नहीं कर पाते कि कौन–सा मूल्य MSP है और कौन -सा बाजार निर्धारित।

महिलाओं में शिक्षा वंचना और अधिक पाई गई। महिला–प्रधान परिवारों में शिक्षा की कमी निर्णय अधिकार को सीमित करती है, जिससे वे मजदूरी और वनोपज संग्रह में अधिक काम करती हैं लेकिन मूल्य निर्धारण में उनकी भूमिका न्यूनतम रहती है। भाषा अवरोध, विशेषकर जनजातीय बोलियों और हिंदी के बीच अंतर, शिक्षा विस्तार में एक संरचनात्मक बाधा बनकर उभरता है। शिक्षकों की अनुपस्थिति और अपर्याप्त शिक्षक संख्या बल भी एक गंभीर चुनौती है। इस प्रकार, शिक्षा वंचना बोड़ला और पंडरिया दोनों में बहुस्तरीय प्रभाव उत्पन्न करती है-आय अस्थिरता, MSP जानकारी का अभाव, योजनागत लाभों तक पहुँच में कठिनाई, कौशल विकास की सीमित क्षमता और स्वास्थ्य-जागरूकता की कमी। शिक्षा की स्थिति ग्रामीण विकास के सभी आयामों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे यह सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का केंद्रीय कारण प्रतीत होती है।

जनसंख्या संरचना

तालिका 4 : जनसंख्या का सारांश

सूचक	परिणाम
आश्रितता अनुपात	100+
लिंगानुपात	संतुलित
आयु संरचना	युवा

भाग-दो

उच्च आश्रितता अनुपात का अर्थ है कि प्रत्येक 100 कार्यशील व्यक्तियों पर 100 से अधिक आश्रित सदस्य हैं, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। यह स्थिति उन क्षेत्रों में अधिक चुनौतीपूर्ण होती है जहाँ आय के स्रोत पहले से ही अस्थिर हों, जैसा कि वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था में अक्सर देखा जाता है। युवा जनसंख्या संरचना अवसर और जोखिम दोनों का

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2025, Revised: 09 Nov 2025, Accepted: 18 Nov 2025, Published: Dec 2025

International Journal of Economic Perspectives,*19* (12) 21-37
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

संकेत देती है। यदि रोजगार उपलब्ध हों तो सामाजिक-आर्थिक उन्नति संभव है, परंतु अवसरों के अभाव में पलायन, गरीबी और असुरक्षा बढ़ने की संभावना रहती है।

लिंगानुपात संतुलित है, जो सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। पर जब इसे सामाजिक निर्णयाधिकार और आर्थिक भागीदारी के संदर्भ में देखा जाता है, तो स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं है। महिलाओं की श्रम-भागीदारी अधिक है, लेकिन आय निर्णय और बाजार पहुंच में उनका अधिकार सीमित है। युवा आबादी और श्रम-प्रधान कृषि वनोपज संरचना के बीच तालमेल है, पर कौशल प्रशिक्षण के अभाव में यह क्षमता उपयोग नहीं हो पाती।

जनसंख्या संरचना स्पष्ट करती है कि यदि क्षेत्र में रोजगार, कौशल विकास और MSP आधारित बाजार स्थिरता प्रस्तुत की जाए, तो जनसंख्या लाभ बन सकती है। अन्यथा यह उच्च आश्रितता और सीमित अवसरों के कारण आर्थिक संकट को और बढ़ा सकती है।

वैवाहिक संरचना

पंडरिया में विवाह की औसत आयु बोड़ला से अधिक है, जो सामाजिक स्थिरता और स्वास्थ्य संकेतकों के लिए बेहतर पाया गया। देर से विवाह करने वाली महिलाओं की पोषण स्थिति और प्रसव-स्वास्थ्य बेहतर पाई गई। बोड़ला के कुछ गाँवों में कम उम्र में विवाह के कारण महिलाओं का श्रम भार अधिक है, जिससे वे वनोपज संग्रहण और मजदूरी में अधिक समय देती हैं पर निर्णय अधिकार सीमित रहता है।

आजीविका संरचना और स्रोत

तालिका 5 : आजीविका भागीदारी

स्रोत	भागीदारी
कृषि	~100%
मजदूरी	~100%
वनोपज	100%
पशुपालन	95%+
गैर–कृषि श्रम	90%+
छोटा व्यापार	10%+

विस्तृत विश्लेषण

अध्ययन दर्शाता है कि बोड़ला और पंडरिया दोनों में आजीविका बहु–स्रोत आधारित है। कृषि और मजदूरी में लगभग 100 प्रतिशत भागीदारी यह बताती है कि कृषि से प्राप्त आय अपर्याप्त है और परिवारों को मजदूरी का सहारा लेना पड़ता है। वर्षा-

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2025, Revised: 09 Nov 2025, Accepted: 18 Nov 2025, Published: Dec 2025

***International Journal of Economic Perspectives*,19 (12) 21-37**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

आधारित कृषि इन दोनों ब्लॉकों में अत्यधिक जोखिमपूर्ण है। सूखा, अतिवृष्टि, कीट-आक्रमण और बाजार मूल्य परिवर्तन आय को प्रभावित करते हैं। इससे मजदूरी एक अनिवार्य पूरक आजीविका बन जाती है।

वनोपज 100 प्रतिशत परिवारों की आय का हिस्सा है। यह न केवल आर्थिक स्रोत है बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं से भी जुड़ा है। पंडरिया में वनोपज आय का हिस्सा बोड़ला की तुलना में अधिक है, जिससे वहाँ आर्थिक जोखिम भी अधिक हैं क्योंकि वनोपज उत्पादन प्रकृति पर निर्भर करता है। जंगलों में दूरी, परिवहन लागत, और बिचौलियों की मौजूदगी मूल्य-हानि को बढ़ाती है।

पशुपालन एक सहायक आय स्रोत है, परंतु चारे की सीमित उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी इसे आर्थिक रूप से स्थायी नहीं बना पाती। निर्माण और ईंट-भट्ठा जैसे गैर-कृषि श्रम में उच्च भागीदारी यह संकेत देती है कि कृषि और वनोपज आय ग्रामीण परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है। पलायन आधारित श्रम विशेष रूप से युवाओं में बढ़ता जा रहा है।

छोटा व्यापार मात्र 10 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि प्रारंभिक पूँजी, बाजार पहुंच और प्रशिक्षण की कमी उद्यमिता को सीमित करती है। पंडरिया में यह अनुपात और कम है, क्योंकि भौगोलिक एकांत और खराब परिवहन संपर्क व्यापारिक गतिविधियों को बाधित करते हैं। MGNREGA मजदूरी आय का महत्त्वपूर्ण स्रोत है, पर भुगतान-विलंब आय-अस्थिरता बढ़ाता है।

इस प्रकार, दोनों ब्लॉकों की आजीविका संरचना स्पष्ट रूप से श्रम-प्रधान, अनिश्चित और जोखिम-संवेदनशील है जिसमें कृषि, मजदूरी और वनोपज-तीनों की निर्भरता मजबूरी से उत्पन्न है, न कि अवसर से। यह स्थिति MSP नीति के प्रभाव को और अधिक महत्त्वपूर्ण बना देती है।

कार्य-दिवस प्रतिरूप

तालिका 7 : कार्य-दिवस पैटर्न

क्षेत्र	कार्य–दिवस स्थिति
बोड़ला	सीमित
पंडरिया	अपेक्षाकृत अधिक

विश्लेषण

बोड़ला में कृषि-मौसम समाप्त होने के बाद मजदूरी कार्य उपलब्ध नहीं होता, जिससे आय में महीनों की अस्थिरता आती है। इसके विपरीत पंडरिया में वनोपज की उपलब्धता अधिक होने से संग्रहण के अवसर और कार्य-दिवस अपेक्षाकृत अधिक

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2025, Revised: 09 Nov 2025, Accepted: 18 Nov 2025, Published: Dec 2025

International Journal of Economic Perspectives,*19* (12) 21-37
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

मिलते हैं। इससे दोनों क्षेत्रों के बीच आय-अंतर पैदा होता है। पंडरिया में अतिरिक्त वनोपज-दिवस एक तरह से सुरक्षा-जाल का कार्य करते हैं, हालाँकि यह भी प्राकृतिक जोखिमों पर निर्भर रहता है।

उपभोग, अवसंरचना और योजनाओं की पहुँच

तालिका 6 : उपभोग व्यय

श्रेणी	स्तर
खाद्य व्यय	उच्च
गैर-खाद्य व्यय	लगभग समान

विश्लेषण

खाद्य और गैर-खाद्य व्यय का लगभग समान होना दर्शाता है कि परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा उपभोग में खर्च कर देते हैं, जिससे बचत की क्षमता नगण्य रहती है (Sen, 1999)। यह स्थिति आर्थिक झटकों-जैसे बीमारी, फसल-विफलता-के दौरान गहरी असुरक्षा उत्पन्न करती है। संचित संपत्ति लगभग न के बराबर पाई गई।

शिक्षा-स्वास्थ्य अवसंरचना

तालिका 8: स्वास्थ्य पहुँच

क्षेत्र	स्थिति
बोड़ला	स्वास्थ्य केंद्र दूर
पंडरिया	पहुँच और कमजोर

विश्लेषण

स्वास्थ्य सेवाओं की दूरी उपचार में देरी, अधिक खर्च और उच्च मृत्यु-जोखिम उत्पन्न करती है। कई प्रसव घर पर होते हैं, जिससे जटिलताओं की आशंका बढ़ जाती है। स्वास्थ्य-अवसंरचना की कमजोरी शिक्षा की कमी से और गंभीर बन जाती है क्योंकि स्वास्थ्य-जागरूकता भी सीमित है।

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2025, Revised: 09 Nov 2025, Accepted: 18 Nov 2025, Published: Dec 2025

International Journal of Economic Perspectives,*19* (12) 21-37
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

ऊर्जा और स्वच्छ जल

लकड़ी आधारित ईंधन से वनों पर दबाव बढ़ता है और महिलाओं का श्रम-भार अत्यधिक हो जाता है। पंडरिया में शौचालय उपलब्धता बहुत कम है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम अधिक हैं। पेयजल स्रोत मौसमी हैं और गर्मी में कई गाँवों में कमी देखी गई।

तालिका 9 : शासकीय योजनाओं की पहुँच

क्षेत्र	कवरेज
बोड़ला	अधिक
पंडरिया	बेहद कम

विश्लेषण

बोड़ला में बैंक दूरी अपेक्षाकृत कम और दस्तावेजे अधिक उपलब्ध पाए गए। पंडरिया में योजनाओं का कवरेज कमजोर है क्योंकि बैंक दूरी, पहचान दस्तावेज़ों की कमी और जागरूकता की कमी बड़ी बाधाएँ बनती हैं। परिणामस्वरूप DBT योजनाएँ और MSP खरीद-केंद्रों का लाभ कम पहुँचता है।

वनोपज निर्भरता एवं MSP प्रभाव

तालिका 10: वनोपज निर्भरता स्तर

क्षेत्र	निर्भरता
बोड़ला	कम-मध्यम
पंडरिया	उच्च (30%+ ग्राम)

विश्लेषण

पंडरिया में कुल आय का लगभग एक-तिहाई वनोपज से प्राप्त होता है। यह प्राकृतिक और बाजार जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। बारिश, तापमान और वन-नीतियों में परिवर्तन संग्रह मात्रा को सीधे प्रभावित करते हैं।

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2025, Revised: 09 Nov 2025, Accepted: 18 Nov 2025, Published: Dec 2025

International Journal of Economic Perspectives,*19* (12) 21-37
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

तालिका 11: MSP जागरूकता

क्षेत्र	MSP जागरूकता
बोड़ला	20% के आसपास
पंडरिया	12–15%

विश्लेषण

कम MSP जागरूकता ग्रामीणों को बिचौलियों के शोषण के प्रति संवेदनशील बनाती है। कई परिवारों को यह भी ज्ञात नहीं कि MSP किस उत्पाद पर लागू है और खरीद-केंद्र कहाँ संचालित होते हैं।

MSP बनाम बाजार मूल्य पर विश्लेषण

MSP और बाजार मूल्य के बीच संबंध वनोपज संग्रहकर्ताओं की वार्षिक आय को सीधे प्रभावित करता है। MSP का उद्देश्य ग्रामीण-जनजातीय आबादी के लिए न्यूनतम आय सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन वास्तविकता में कई उत्पादों में MSP और बाजार मूल्य के बीच अंतर महत्वपूर्ण पाया गया। यह अंतर दो प्रकार का हो सकता है:

(1) **MSP बाजार से अधिक** – इससे लाभ होता है, पर मात्रा सीमित होने से कुल लाभ कम रहता है।

(2) **MSP बाजार से कम** – इससे ग्रामीणों को हानि होती है और वे बाजार-शोषण के प्रति अधिक कमजोर होते हैं।

उत्पाद-वार विश्लेषण

।.**लाख और शहद:** इन उत्पादों में MSP बाजार कीमत से अधिक पाया गया। परंतु इनका संग्रहण विशेष कौशल, मौसम और उपलब्धता पर निर्भर है। संग्रहण मात्रा सीमित होती है, जिससे कुल वार्षिक आय पर इसका प्रभाव मध्यम रहता है। पंडरिया के कुछ गाँवों में लाख संग्रहण अच्छा है, लेकिन उत्पादन वर्ष–वार बदलता रहता है। भंडारण और गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं की कमी कीमत को गिरा देती है।

साल बीज: MSP साल बीज पर आकर्षक माना जाता है, परंतु बाजार में कीमत कभी-कभी इससे अधिक हो जाती है। ग्रामीण अक्सर तत्काल नकद भुगतान को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए MSP खरीद केंद्र पर जाने के बजाय बाजार में बेच देते हैं। इससे MSP का उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

चरोटा, वनजीरा, डोरी, इमली: इन उत्पादों में MSP बाजार दर की तुलना में काफी कम पाया गया। स्थानीय बाजारों में इनका मूल्य अधिक है क्योंकि इनका उपयोग मसालों, औषधियों और परंपरागत उत्पादों में होता है। MSP

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2025, Revised: 09 Nov 2025, Accepted: 18 Nov 2025, Published: Dec 2025

International Journal of Economic Perspectives,*19* **(12) 21-37**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

कम होने से ग्रामीण बाजार पर निर्भर रहते हैं और बिचौलिये कम कीमत देते हैं। परिणामस्वरूप इन उत्पादों में स्पष्ट आर्थिक हानि मिलती है।

ग्रेडिंग और भंडारण के प्रभाव: वनोपज का मूल्य उसकी ग्रेडिंग, नमी, पैकेजिंग और भंडारण गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक सुखाई और पैकेजिंग सुविधाओं की कमी है। इससे बाजार में उत्पाद की गुणवत्ता कम आंकी जाती है और कीमत घट जाती है। MSP खरीद केंद्र भी अक्सर ग्रेडिंग के अभाव में उत्पादों की गुणवत्ता सीमित कर लेते हैं।

मूल्य–सूचना की कमी: यह पाया गया कि MSP–सूचना ग्रामीणों तक समय पर नहीं पहुँचती। परिणामस्वरूप वे बिचौलियों द्वारा बताए गए गलत बाजार मूल्य पर भरोसा कर लेते हैं। मूल्य–सूचना का अभाव बाजार–शोषण का प्रमुख कारण है (Saxena, 2020)।

नीति-प्रभाव: MSP नीति का वास्तविक प्रभाव कमजोर पाया गया क्योंकि खरीद केंद्रों की उपलब्धता, परिवहन लागत, जागरूकता और त्वरित नकद भुगतान की अनुपस्थिति ग्रामीणों को बाजार की ओर धकेलती है। इससे MSP का सुरक्षा जाल प्रभाव अपूर्ण रह जाता है।

MSP कई उत्पादों में लाभकारी होते हुए भी पर्याप्त आय स्थिरता प्रदान नहीं कर पाता क्योंकि (1) उत्पाद वार मात्रा सीमित है, (2) बाजार असंगति अधिक है, (3) सूचना और पहुँच कमजोर है, और (4) प्रसंस्करण क्षमता का अभाव है। इसलिए MSP का लाभ कम और जोखिम अधिक बना रहता है।

अध्ययन की सीमाएँ

अध्ययन क्षेत्रीय परिस्थितियों को समग्र रूप से समझने का प्रयास करता है, फिर भी कुछ सीमाएँ बनी रहती हैं। पहला, प्राथमिक डेटा गोपनीयता दिशानिर्देशों के कारण केवल समेकित रूप में प्रस्तुत किया जा सका, जिससे व्यक्तिगत–स्तर की विविधता को विस्तार में शामिल करना संभव नहीं था। दूसरा, वनोपज की उपलब्धता वर्ष वार जलवायु पर निर्भर होने से कुछ परिणाम प्राकृतिक उतार–चढ़ाव के भीतर देखे जाने चाहिए; मौसमीय जोखिम के कारण पंडरिया और बोड़ला के बीच संग्रहण असमानता समय के साथ बदल सकती है। तीसरा, MSP खरीद-केंद्रों की मौसमी उपलब्धता से संबंधित डेटा पूरी तरह संग्रहित नहीं किया जा सका, क्योंकि केंद्र वर्ष में सीमित अवधि के लिए सक्रिय रहते हैं। चौथा, परिवहन लागत और बिचौलिया दक्षता के सूक्ष्म स्तर पर मूल्यांकन का विस्तृत मात्रात्मक अध्ययन इस शोध के परिधि में संभव नहीं था। पाँचवां, अध्ययन महामारी काल के तुरंत बाद संचालित हुआ, जिससे कुछ आजीविका पैटर्न अस्थायी हो सकते थे। इन सीमाओं के बावजूद शोध स्थानीय आजीविका संरचना, MSP प्रभाव, वनोपज निर्भरता और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बीच वास्तविक संबंधों को स्पष्ट रूप से सामने लाता है।

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2025, Revised: 09 Nov 2025, Accepted: 18 Nov 2025, Published: Dec 2025

International Journal of Economic Perspectives,*19* (12) 21-37
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

नीतिगत सुझाव

अध्ययन से प्राप्त आँकडें दर्शाते हैं कि वनोपज-आधारित आजीविका को स्थिर और न्यायसंगत बनाने हेतु नीतिगत हस्तक्षेप अनिवार्य है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वनोपज-आधारित आजीविका को स्थिर और न्यायसंगत बनाने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप जरूरी है। सबसे पहले, MSP को वार्षिक रूप से बाजार के अनुरूप अद्यतन किया जाना चाहिए, विशेषकर चरोटा, डोरी, वनजीरा और इमली जैसे उत्पादों के लिए, जिनका बाजार मूल्य लगातार MSP से अधिक पाया गया। इसके साथ ही SHG आधारित स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जानी चाहिए ताकि महुआ, साल बीज, चार बीज और शहद जैसे उत्पादों में मूल्य-वृद्धि हो सके और ग्रामीणों को अधिक लाभ मिल सके। एक डिजिटल वन-उत्पाद मूल्य सूचना प्रणाली (FD-PIN) विकसित करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से MSP, बाजार मूल्य, खरीद-केंद्रों की उपलब्धता, गुणवत्ता मानक और संग्रहण तिथियों की जानकारी सीधे मोबाइल या ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराई जा सके। महिला SHG को MSP खरीद-केंद्र संचालन और ग्रेडिंग-पैकेजिंग गतिविधियों में प्राथमिक भूमिका देने से न केवल पारिवारिक आय बढ़ेगी, बल्कि निर्णयाधिकार और सामाजिक-सशक्तिकरण भी मजबूत होगा। युवाओं के लिए MFP ग्रेडिंग, वैल्यू एडिशन, प्रसंस्करण, विपणन और वन-आधारित उद्यमों के प्रबंधन पर कौशल-प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए, जिससे पलायन-निर्भरता कम हो सके। अवसंरचना के क्षेत्र में पंडरिया में सड़क, बाजार-पहुंच, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार आवश्यक है, साथ ही योजनागत लाभों तक पहुँच बढ़ाने के लिए डिजिटल दस्तावेज़ प्रणाली भी विकसित की जानी चाहिए। अंत में, MGNREGA भुगतान प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने की जरूरत है ताकि मजदूरी भुगतान में विलंब न हो और ग्रामीण परिवारों की नकदी-अस्थिरता कम हो।

I. **MSP का वार्षिक बाजार-संगत अद्यतन**

चरोटा, डोरी, वनजीरा और इमली जैसे उत्पादों के MSP तुरंत बढ़ाए जाएँ, क्योंकि इनका बाजार मूल्य लगातार MSP से अधिक है।

II. **SHG आधारित प्रसंस्करण और मूल्य-वृद्धि इकाइयाँ**

महुआ, साल बीज, चार बीज और शहद के लिए स्थानीय प्रसंस्करण–केंद्र स्थापित किए जाएँ ताकि ग्रामीणों को उच्च मूल्य प्राप्त हो सके।

III. **वन-उत्पाद मूल्य सूचना प्रणाली (FD-PIN)**

डिजिटल सूचना-तंत्र तैयार कर MSP, बाजार मूल्य, खरीद–केंद्र स्थिति, गुणवत्ता मानकों और संग्रहण तिथियों की जानकारी मोबाइल-SMS और ग्राम पंचायतों तक पहुँचाई जाए।

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2025, Revised: 09 Nov 2025, Accepted: 18 Nov 2025, Published: Dec 2025

***International Journal of Economic Perspectives*,19 (12) 21-37**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

IV. **महिला SHG की भूमिका बढ़ाना**

MSP खरीद–केंद्र संचालन और ग्रेडिंग-पैकेजिंग गतिविधियों में महिला समूहों को प्राथमिक भूमिका दी जाए। इससे पारिवारिक आय, निर्णयाधिकार और सामाजिक-सशक्तिकरण में सुधार होगा।

V. **युवा कौशल-प्रशिक्षण**

MFP ग्रेडिंग, वैल्यू-एडिशन, प्रसंस्करण, विपणन और बागवानी-आधारित वनों के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएँ, जिससे पलायन-निर्भरता कम हो सके।

VI. **अवसंरचना सुधार**

पंडरिया में सड़क, बाजार-पहुंच, बैंकिंग और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। योजनागत लाभ हेतु डिजिटल दस्तावेज़ प्रणाली स्थानीय स्तर पर विकसित की जाए।

VII. **MGNREGA भुगतान सुधार**

विलंब कम करने हेतु भुगतान-स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ताकि ग्रामीण परिवारों की नकदी अस्थिरता घटे।

निष्कर्ष

यह अध्ययन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बोड़ला और पंडरिया दोनों सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में हैं, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और आय स्थिरता के संदर्भ में। वनोपज आय इन क्षेत्रों के लिए बैगा पारिवारिक अर्थव्यवस्था का अनिवार्य स्तंभ है, परंतु इसकी प्रकृति जोखिम संवेदनशील है। MSP नीति संरचनात्मक रूप से लाभकारी है, लेकिन इसकी वास्तविक प्रभावशीलता स्थानीय स्तर पर सीमित पाई गई क्योंकि जागरूकता कम है, खरीद केंद्रों की पहुँच बाधित है और कई उत्पादों में MSP बाजार दर से कम है। पंडरिया की जोखिम संवेदनशीलता बोड़ला से अधिक है क्योंकि वनोपज निर्भरता लगभग एक तिहाई आय का आधार बनती है और वहाँ योजनागत पहुँच तुलनात्मक रूप से कमजोर है। अध्ययन यह इंगित करता है कि यदि MSP को बाजार संगत बनाया जाए, स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयाँ विकसित की जाएँ, मूल्य सूचना तंत्र लागू किया जाए, और महिला व युवा समूहों को संस्थागत भूमिका दी जाए, तो क्षेत्र की आजीविका सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार संभव है। यह शोध नीति निर्माताओं, विकास एजेंसियों और शैक्षणिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण प्रमाणिक आधार प्रस्तुत करता है और वनोपज आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर, उत्पादक और न्यायसंगत विकसित करने की दिशा में ठोस संकेत प्रदान करता है।

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2025, Revised: 09 Nov 2025, Accepted: 18 Nov 2025, Published: Dec 2025

International Journal of Economic Perspectives,*19* **(12) 21-37**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

संदर्भ सूचि

1. Banerjee, S., & Behera, M. (2019). Forest dependence and livelihood vulnerability in tribal regions. *Journal of Tribal Studies*, 12(2), 45–58.

2. Census of India. (2011). *Primary Census Abstract*. Government of India.

3. Forest Department of Chhattisgarh. (2020). *Annual Forest Report*.

4. Gupta, R., & Kant, S. (2018). Non-timber forest products and rural livelihoods in India. *Forest Policy Review*, 9(1), 23–39.

5. IIFM. (2020). *Minor Forest Produce Value Chain Study*. Indian Institute of Forest Management.

6. Kumar, R. (2017). Tribal livelihoods and market access constraints. *Indian Journal of Social Development*, 14(3), 101–118.

7. Mahapatra, A. (2016). Forest produce, income security and tribal economy. *Development Economics Review*, 8(4), 66–79.

8. Meena, K. (2015). Education and tribal marginalization in rural India. *Social Scientist*, 43(7), 55–72.

9. Ministry of Tribal Affairs. (2021). *MFP Policy Implementation Report*. Government of India.

10. MoSPI. (2020). *Education and Development Indicators Report*.

11. Patel, G. (2022). MSP policy and tribal welfare outcomes. *Economic Outlook*, 17(2), 88–102.

12. Rao, D. (2019). Women, NTFPs and forest livelihoods. *Gender and Development*, 26(1), 92–110.

13. Rai, S., & Tandon, P. (2018). Impact of minimum support price on tribal incomes. *Journal of Rural Policy Studies*, 6(3), 117–131.

14. Sahu, R. (2018). Market intermediaries in the forest-produce trade. *Rural Economy Journal*, 11(2), 77–90.

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2025, Revised: 09 Nov 2025, Accepted: 18 Nov 2025, Published: Dec 2025

***International Journal of Economic Perspectives*,*19* (12) 21-37**
ISSN: 1307-1637 UGC CARE GROUP II
Retrieved from https://ijeponline.com/index.php/journal

15. Saxena, N. C. (2020). Governance gaps in forest-based markets. *Indian Forest Governance Report*.

16. Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

17. Sharma, V. (2017). Ecological risks and NTFP collection patterns. *Ecology and Society*, 15(3), 112–124.

18. Singh, P. (2022). Tribal welfare schemes and implementation gaps. *Policy Review Quarterly*, 5(1), 19–34.

19. TRIFED. (2022). *MFP Procurement Annual Report*. Government of India.

20. Tiwari, S. (2021). Tribal economy and forest–produce dependence. *Journal of Rural Studies*, 29(4), 211–227.

© 2025 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2025, Revised: 09 Nov 2025, Accepted: 18 Nov 2025, Published: Dec 2025